Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to include education, economic, social and caste-wise data for conducting population census - 2021.

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): माननीय सभापति महोदय, किसी भी विकासशील देश की उन्नति तभी रफ्तार पकड़ती है, जब उस देश में रह रहे लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों । इसके लिए सरकार नई नीतियाँ और योजनाएं बनाती रही हैं । लेकिन कई बार ये योजनाएं और नीतियाँ विफल साबित हुई हैं । इसका कारण यह है कि सरकार के पास जनगणना के सही आंकड़े नहीं हैं । यह जनगणना सही तरीके से नहीं की गई है ।

महोदय, देश की आजादी से पहले भी जातीय आधार पर जातिवार जनगणना होती थी । वर्ष 1941 में जातीय आधार पर जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण उसे घोषित नहीं किया जा सका । भारत में आखिरी जाति-आधारित जनगणना ब्रिटिश हुकूमत के दौरान वर्ष 1931 में हुई थी । वर्ष 1931 तक सभी जातियों की गिनती होती थी । अभी तक उसी आंकड़े से काम चल रहा है । उसी आंकड़े के आधार पर बताया गया है कि देश में ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत है । जनगणना की रिपोर्ट में सभी जातियों की संख्या और उसकी शैक्षिक-आर्थिक हालात का ब्यौरा होता है । जब देश में पशुओं की गणना भी होती है, लेकिन देश में अलग-अलग प्रकार के कितने पशु हैं, गाय, भैंस, बकरा आदि सभी की गणना हो सकती है, लेकिन अभी तक देश के लोगों की जातिवार जनगणना नहीं हो पाई है ।

महोदय, ज्ञात हो कि बिहार में जदयू और भाजपा की साझा सरकार है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है ।

वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी । उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दल मांग करते रहे कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए । आपके माध्यम से मुझे यह भी बताना है कि मोदी जी की सरकार में ही इतनी साहस

और हिम्मत थी कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी के ऐतिहासिक पंचतीर्थ स्थल बनवाए तथा दलितों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए संविधान में भी संशोधन किया गया ।

माननीय सभापति : आप अपनी मांग बताइए । आप क्या चाहते हैं?

श्री मुकेश राजपूत : इसके साथ ही, सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10 परसेंट आरक्षण दिया गया । इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे सभी वर्गों को संवैधानिक अधिकार मिला ।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पुन: एक ही बात का अनुरोध करता हूं । वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना को शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ जातिवार जनगणना कराने का आग्रह तैयार किया जाए, जिससे राष्ट्रीय योजनाओं का सभी वर्गों को लाभ मिल सके । धन्यवाद ।